

हिन्दुस्तान

हताशा की राजनीति

सियासत जब रास्ता भटकती है, तो वह अक्सर उन्हीं तंग गलियों में पनाह लेती है, जहां आम आदमी पार्टी की नेता और गाजियाबाद से पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी देखी गई हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कुछ मुस्लिम नेताओं को बातचीत के दौरान यह नसीहत बांट रही हैं कि मुसलमान बहुत सेकुलर हैं और उनके वोट बंट जाते हैं, उन्हें ‘कम्युनल’ हो जाना चाहिए। इसी के बरक्स कई और आवाजें भी सुनने को मिली हैं, जो प्रवीण तोगड़िया से लेकर रामदास कदम की जवानों से निकली हैं। चुनाव आयोग इन सबका संज्ञान ले रहा है और उनके खिलाफ उचित कदम भी उठा रहा है। यह भी सुखद है कि शाजिया के इस आपत्तिजनक कृत्य की उनकी पार्टी ने भी आलोचना की है, तो उधर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने अपने अति-उत्साही समर्थकों व सहयोगियों के बयानों की निंदा की है। यह सचमुच अफसोस की बात है कि इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी हमारे पढ़े-लिखे नुमाइदे धर्म और जाति की भाड़ेबंदी को मजबूत करने में जुते हैं।

शाजिया इल्मी का एक वीडियो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी मीडिया में बहुत उछला था और तब पार्टी ने उसे प्रायोजित बताकर न सिर्फ उनका बचाव किया था, बल्कि उनकी उम्मीदवारी भी बरकरार रखी थी, हालांकि बहुत थोड़े से मतों से शाजिया वह चुनाव हार गई थीं। यकीनन उस विवाद ने उन्हें कुछ न कुछ चुनावी नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद यह नया वीडियो बताता है कि हमारे युवा नेता भी पुरानी गलतियों से कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की कुलममा पूंजी उनकी ईमानदारी ही है, और सिर्फ आर्थिक कसौटी पर नहीं, बल्कि वैचारिक और आचरण की कसौटी पर भी यह ईमानदारी परखी जाएगी।

ऐसे में, इस तरह के मामलों में पार्टी को तत्परता से और ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इनका असर उसकी साख पर पड़ता है। अपने धर्म और जाति की चिंता करना कतई गलत नहीं है, अगर वह देश और समाज की भलाई से प्रेरित हो। मुस्लिम बच्चों की तालीम और सेहत, औरतों की बेहतरी और पसमांदा जमातों की तरक्की की भी सियासत की जा सकती है। लेकिन यह राजनीति आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको उनके दुख-दर्द, उनकी परेशानियों के बीच जीना पड़ता है। इस स्थिति से बचने के लिए ही अक्सर वे सुलभ हथियार आजमाए जाते हैं, जो अब अपनी धार खो चुके हैं और उनमें पहले-सी चमक भी नहीं रही।

इस देश के लिए यह गर्व की बात है कि इसके बहुसंख्य लोग, जो हर मजहब, जाति, समुदाय और क्षेत्र से रिश्ता रखते हैं, गंगा-जमनी तहजीब के हिमायती हैं। दुनिया में हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा और उसकी तरक्की का यह मजबूत आधार है और इस सांस्कृतिक जमीन को हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से इस लायक बनाया है कि सब एक साथ फले-फूलें। इसलिए किसी को भी यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वह इसमें विषबेल बोने की कोशिश करे। इस बार के चुनाव में नेताओं के निजी हमलों और धुवीकरण वाले बयानों की बाढ़-सी आ गई है। यह भविष्य की राजनीति के लिहाज से चिंतित करने वाली बात है। चुनाव आयोग को लक्षमण रेखा पर करने वालों के विरुद्ध और कठोर कार्रवाई करनी होगी। यह इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक कटुता से उभजे जन-प्रतिनिधि विधायी संस्थाओं की गरिमा का भी खयाल नहीं रखेंगे। हम देख ही रहे हैं कि असहिष्णु रवैये के कारण संसद ठीक से काम नहीं कर पा रही। इसलिए हमें आज विभाजक राजनीति के पैरोकारों की नहीं, समन्वयवादी नेताओं की जरूरत है।

विदेशी अखबार से

धर्म और राजनीति

ऐतिहासिक तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री धर्म को खुद तक महदूद रखते रहे हैं। मगर डेविड कैमरन ने पिछले दिनों *चर्च टाइम्स* से कहा कि यह मेरी ईसाइयत ही है, जिसने मुझे लोगों की ज़िंदगी संवराने की कोशिश के लिए प्रेरित किया। कैमरन ने कहा कि जो लोग ‘धर्मनिरपेक्ष तटस्थता’ को अपनाते हैं, वे उसके नतीजे को समझने में नाकाम रहते हैं, हालांकि उन्होंने उन परिणामों की व्याख्या नहीं की। कैमरन ने ईसाई परंपराओं के प्रति अपनी गहरी आस्था को अभिव्यक्त करने के साथ ही एक ईसाई आत्मविश्वासी देश की वकालत भी की। पिछले दिनों कैमरन ने अपने धार्मिक विश्वास की चर्चा करते हुए यह कहा था कि वह एक प्रतिबद्ध ईसाई हैं और स्थानीय चर्च के दिखाए रास्ते पर चलकर उन्होंने भरपूर शांति और मदद पाई है। बहुत मुमकिन है कि ईस्टर के दौरान के ये शाब्दिक हस्तक्षेप दरअसल

गरीबी को लेकर बिशपों की आलोचना का मार्मिक जवाब हो। दरअसल, एक व्यापक सोच तो यही है कि कैमरन के ये बयान theguardian मौकापरस्त सियासी कौशल का हिस्सा है, जिसके जरिये वह अपने महत्वपूर्ण टोरी वोटरों को रझाना चाहते हैं। जिस तरह से कैमरन ने सम्मेलंगिक विवाह के पक्ष में काानून बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और यूकिए (यूके इंटीग्रेटेड पार्टी) के साथ नजदीकियां बढ़ाई, उनको देखकर टोरी वोटर अन्न तक हैरत में हैं। लेकिन इन दिनों किसी भी दौर की तुलना में आस्था अधिक विवादस्पद मसला बन गया है। ऐसे में, एक कुशल राजनीतिज्ञ दिखने की बजाय कैमरन ने एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है। वैसे डेविड कैमरन पहले कंजर्वेटीव प्रधानमंत्री नहीं हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट किया। मागीट थैचर ने भी 1985 में ‘फेथ इन द सिटीज’ के प्रकाशन के बाद अपना धार्मिक विश्वास जताया था। इस रिपोर्ट को आर्कबिशप रॉबर्ट रसी ने तैयार किया था, जो थैचर की नीतियों के बड़े आलोचक थे। यदि कैमरन का तर्क यह है कि उनका मूल भाव सही है, इसलिए उनके कदम उचित हैं, तो इसे काफी हद तक पारंपरिक राजनीति के चरम से ही देखा जा सकता है। फिर भी यह आपत्तिजनक दर्शन ही कहलाएगा।

द गार्शियन, ब्रिटेन

75 साल पहले

हिन्दुस्तान

सेठ जी का वजन और घटा

जयपुर, २२ अप्रैल। १९ अप्रैल को सेठ जमनालाल जी के बड़े लड़के श्री कमलनयनजी उनसे गढ़मौरा में मिले। सेठजी को कोई साथी नहीं दिया गया है। गत एक दो सप्ताह से ५ पाँड वजन और घट गया है और ता. १५ से वह केवल फल व दूध खाते हैं, जिससे कमजोरी महसूस होती है। पानी उबाल कर पीते हैं। गरमी भी अधिक पड़ने लगी है। लाम्बा में जहरीले सांप, काले भयंकर बिच्छू, कनखजुरे खूब निकलते हैं। गरमी की अधिकता होने के कारण सांप आदि का निकलना रोजाना हो गया है। कई बिस्तरों में सांप निकल चुका है। इससे वहां रहने वाले राजकर्मचारियों और राजबंदियों की जान सदा खतरे में रहती है। समझ में नहीं आता कि क्या रात में राजबंदियों के रखने के लिए दूसरा कोई उपयुक्त स्थान नहीं है जो उन्हें ऐसे पुराने भयंकर स्थान में ही रखा जा रहा है। कुछ लोग इसी कारण से इस नीति को संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। लाम्बा में पहले अंग्रेजी पत्रों के साथ हिन्दी पत्र भी भेज देने की इजाजत थी। कई दिनों में हमेशा की भांति हिन्दी का पत्र ‘प्रजा मित्र’ पुलिस के दफ्तर में लाम्बा पहुंचाए जाने के लिए रख दिया जाता था और अखबार को पुलिस लाम्बा पहुंचा देती है, परंतु प्रजामित्र नहीं। उसे रोक लेने का कारण कोई नहीं बतलाया गया है।

23 अप्रैल, 1939 को प्रकाशित

चुनाव आयोग की और भी हैं चुनौतियां

देश के सबसे विश्वसनीय संगठनों में शामिल चुनाव आयोग को दोषरहित मतदाता

सूची बनाने के अलावा आदर्श आचार संहिता पर भी काम करने की जरूरत है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि हाल के समय में मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। यह रुझान न केवल मौजूदा लोकसभा चुनाव के उन संसदीय क्षेत्रों में दिखा, जहां मतदान हो चुके हैं, बल्कि हाल के वर्षों में हुए विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला। शायद ही इससे किसी को असहमति हो सकती है कि यह काफी हद तक चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका से संभव हो पाया है। साथ ही, शायद ही ऐसा कोई संसदीय क्षेत्र हो, जहां इस बार मतदान का प्रतिशत साल 2009 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत से कम रहा हो। वैसे, किसी को भी इस बढ़ोतरी पर चौंकने की



उमाशंकर शुक्ल

नशतर

माफी और टॉफी का सियासी मनोरंजन

जनता को न माफ़ी चाहिए, न टॉफी। उसे जो चाहिए, वह न उनके कने है, न इनके।

इन दिनों माफी और टॉफी पर सियासत गरम है। गरम सियासत के बहाने एक-दूसरे को ‘पटकनी’ देने के रस्ते तलाशो जा रहे हैं। माफी वाले इस ज़िद पर अड़े हैं कि एक ही बात के लिए बार-बार माफी मांगने से क्या फायदा और टॉफी वाले यह यकीन करवाने में लगे हैं कि उनके कने सिर्फ ‘टॉफी मॉडल’ है। लुरफ़ यह है कि जनता को न मतलब उनकी माफी से है, न इनकी टॉफी से। उसे जिस बात से मतलब है, वह बात न उनके कने है, न इनके। फिर भी दोनों का दावा यही है कि जनता की फ़िक्र उन्हें ही है।

हालांकि, माफी मांग लेने से कोई छोट या मोटा नहीं हो जाता, मगर क्या कीजिएगा, जब उनकी डिक़्शनरी में माफी शब्द ही नहीं। ऐसा

साइबर संसार

बहू-बेटियों की पीड़ा

त्रिपुरा से तोस हजार रुपये में खरीदकर हरियाणा लाई गई रत्ना पृथ्वी हैं, ‘आज जैसे ईसान, वैसे मैं भी ईसान। तो ईसान को ईसान समझना चाहिए न?’ बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही मार डालने का समाधान जिस समाज ने अपनाया हो, उससे रत्ना ईसानियत की उम्मीद कर रही है। पंजाब-हरियाणा के कई इलाकों को जब अनचाही बेटियों से मुक्ति मिल गई, तो एक नई समस्या ने जन्म लिया कि बहुओं की तलाश मुश्किल होती गई। इसका समाधान भी निकाला गया। यह समाधान भी उतना ही अमानवीय है, जितनी समस्या की असली वजह। बाबा रामदेव हरियाणा के जिस जिले से आते हैं, उसका नाम एक और वजह से रोशन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की तादाद यहां देश भर में सबसे कम है, यानी प्रति हजार पुरुष के अनुपात में सिर्फ 761 महिलाएं हैं। खाली जगह भरने के लिए रत्ना जैसी लड़कियां मवेशियों की तरह और अक्सर मवेशियों से भी कम कीमत में खरीदी-बेची जा रही हैं।

28 साल की रत्ना जरखरीद गुलाम है, जिसका मनचाहा इस्तेमाल करने की आजादी उसका पति कहे जाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी और को भी है। बड़े-बुजुर्ग अक्सर सब कुछ जानते हुए चुप रहते हैं। बिकने के लगभग 11 साल बाद रत्ना के दो बेटे हैं, लेकिन खरीदार अब रत्ना को रखने के लिए तैयार नहीं हैं। रत्ना बताती हैं, ‘अब कहते हैं कि लड़कों को यहां छोड़कर त्रिपुरा वापस चली जा।’

बीबीसी में वर्तिका	
	
मेल बॉक्स	
	
गांव का हाल	
अमेठी के पास ही एक गांव है जायस, जो अब एक छोट कस्बे का रूप लेता जा रहा है। यहीं से कुछ दूर वीरान जगह पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी का घर है, जो अब लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। आलीशान कमरों में मकड़ी केजाले लग चुके हैं। दीवारें गिर रही हैं। रात के समय यह घर नशीदियों, जुआरियों और अन्य असामाजिक तत्वों की आशान-स्थली बन जाता है। अगर दिन में इस इमारत में जाएं, तो शराब की खाली बोतलें और नशीले पदार्थ मिलते हैं। मकान के आसपास मलबा और कूड़े-करकट का अंबार लगा हुआ है। जायस में विकास का कोई निशान नहीं दिखता। न तो केंद्र सरकार की नजर यहां पड़ी है, न ही	

राज्य सरकार की। अगर सब कुछ यों ही चलता रहा, तो यह ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाएगी।

जसवंत सिंह

शांतिकुंज, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग

आजकल जन-जागरूकता काफी बढ़ गई है, मीडिया की पैनी नजर है, इसलिए राजनेता अपने पुराने कारनामों पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकतर नेता अपने या अजीज लोगों के भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हैं। इसलिए इसमें से कुछ राजनेता भ्रष्टाचार को सामाजिक और कुछ वैश्विक समस्या बताते हैं। पर ये यह नहीं बताते हैं कि यह सामाजिक समस्या कहां से आई? ऐसे समय में, जब जनता यह जानने में लगी है कि व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक किनरा

जरूरत नहीं है और न ही इसका कोई विशेष मतलब निकाला जाना चाहिए।

मतदाताओं को जागरूक बनाने के विभिन्न अभियानों के लिए चुनाव आयोग को सभी चीजों का श्रेय मिलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों की पहल चुनाव आयोग ने की थी। इसके अलावा, मतदाता सूची को दोषरहित बनाने के लिए भी अभियान चलाए गए और इसीलिए काफी सारे फर्जी नाम इससे हट पाए। इन सबसे मतदान प्रतिशत में अच्छा-खासा इजाफा हुआ। लेकिन ठीक इसी समय में चुनाव आयोग को उन गलतियों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, जिनके चलते असली मतदाताओं के नाम हट गए, जबकि वे कई वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। इस तरह की शिकायतें सिर्फ एक-दो पोलिंग बुथों से नहीं, बल्कि कई पोलिंग स्टेशनों से आई हैं। हालांकि, यह समय चुनावों में जन-भागीदारी के बढ़ने के जश्न मनाने का है, लेकिन कुछ चुनाव अधिकारियों की लापरवाही के कारण मतदाता सूची से काफी लोगों के नाम का हट जाना भी चिंता की बात है।

बहरहाल, उच्च मतदान प्रतिशत दरअसल उस रुझान की ही निरंतरता है, जिसकी शुरुआत हाल के विधानसभा चुनावों में हुई थी। गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 फीसदी से अधिक टर्न-आउट रहा। दूसरे राज्यों, जैसे बिहार, कर्नाटक, मणिपुर और तमिलनाडु में यह वृद्धि सात-आठ प्रतिशत तक रही। लेकिन इस इजाफे का अधिक मतलब निकालना जोखिम भरा है, क्योंकि यह इस बात का आवश्यक संकेत नहीं कि भारी मतदान बदलाव के लिए ही हुए हैं। अतीत में हम देख चुके हैं कि विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कई सूबों में सत्तारूढ़

ऐसे चुनाव से क्या फायदा, जिसमें

मनोरंजन न हो। कम से कम हमारे देश में तो बेरिंग चुनाव नहीं ही लड़े जाते।

माफी और टॉफी की बहस के बीच एक नया

जुमला उल्टू बनने-बनाने का भी फिट कर दिया गया है। जो आजकल बेहद हिट है। हमें अपने देश के नेताओं का ‘एहसानमंद’ होना चाहिए कि उन्होंने चुनावी-राजनीति को गंभीरता से मुक्त करके उसे मनोरंजन युक्त बना दिया है। मतदात हर नेतल लगा हुआ है अपने-अपने तरीके से जनता का मनोरंजन करने और हमें लिखने का ‘मसाला’ देने में।

अंशुमाली रस्तोगी

मनसा वाचा कर्मणा

अनमोल आभूषण

वाल्मीकि *रामायण* की कथा में जब राम-लक्ष्मण और उनकी वानर सेना द्वारा लंका में प्रवेश के लिए समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध किया गया और समुद्र देव ने बहुत देर तक उनके अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया, तब राम समुद्र पर क्रोधित होकर कहते हैं- ‘समुद्र को अपने ऊपर अहंकार है, इसलिए वह प्रकट नहीं हो रहे हैं। शांति, क्षमा, सरलता और मधुरता, ये सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही हाल होता है। गुणहीन लोग गुणवानों के गुणों के कारण उन्हें असमर्थ समझ लेते हैं। लेकिन जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट, धृष्ट और सर्वत्र धावा बोलने वाला, अच्छे-बुरे को कठोर दंड देने वाला होता है, उस मनुष्य का सभी सत्कार करते हैं।’

क्रोधित राम ने लक्ष्मण से समुद्र को सोखने के लिए धनुष मांगा, लेकिन लक्ष्मण ने राम को समुद्र पर क्रोध न करने की नीति का स्मरण करवाकर बाण चलाने से रोक लिया। यह प्रसंग दर्शाता है कि सज्जनों के सौम्य व्यवहार और मीठी वाणी को दुष्टजन उनकी दुर्बलता समझ बैठते हैं। आजकल शांत और सौम्य पुरुष को मूर्ख समझा जाता है और नीतिगत बातें करने वालों को अव्यावहारिक। इसलिए तो माता-पिता भी चुस्त, चालाक और कड़वी जबान बोलने वाले बच्चों को पसंद करने लगे हैं। ऐसी संतानों के साथ वे अपने को सुरक्षित समझते हैं। काल कोई भी हो, सतयुग या कलयुग, सज्जन और दुर्जन समाज में हमेशा ही रहते हैं। लेकिन जीत गुणवाणता की ही होती है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व के गुणों से समाज का भला होता है, स्वयं उसका नहीं। गुणहीनों द्वारा असमर्थ समझे जाने पर भी गुणी मनुष्यों को अपने समाजोपयोगी गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। समुद्र पर आए राम के क्रोध को लक्ष्मण ने शांत कर दिया था। वह समुद्र सोखने के अपराध से वंचित रहे। आज भी कुसंस्कारी लोगों के उकसाने पर कभी-कभी सत्पुरुष अपना धैर्य खोने लगते हैं। उन्हें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए।

गुदुला सिन्हा	
	
बीबीसी में वर्तिका	
	
मेल बॉक्स	
	
गांव का हाल	
अमेठी के पास ही एक गांव है जायस, जो अब एक छोट कस्बे का रूप लेता जा रहा है। यहीं से कुछ दूर वीरान जगह पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी का घर है, जो अब लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। आलीशान कमरों में मकड़ी केजाले लग चुके हैं। दीवारें गिर रही हैं। रात के समय यह घर नशीदियों, जुआरियों और अन्य असामाजिक तत्वों की आशान-स्थली बन जाता है। अगर दिन में इस इमारत में जाएं, तो शराब की खाली बोतलें और नशीले पदार्थ मिलते हैं। मकान के आसपास मलबा और कूड़े-करकट का अंबार लगा हुआ है। जायस में विकास का कोई निशान नहीं दिखता। न तो केंद्र सरकार की नजर यहां पड़ी है, न ही	

राज्य सरकार की। अगर सब कुछ यों ही चलता रहा, तो यह ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाएगी।

जसवंत सिंह

शांतिकुंज, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग

आजकल जन-जागरूकता काफी बढ़ गई है, मीडिया की पैनी नजर है, इसलिए राजनेता अपने पुराने कारनामों पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकतर नेता अपने या अजीज लोगों के भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हैं। इसलिए इसमें से कुछ राजनेता भ्रष्टाचार को सामाजिक और कुछ वैश्विक समस्या बताते हैं। पर ये यह नहीं बताते हैं कि यह सामाजिक समस्या कहां से आई? ऐसे समय में, जब जनता यह जानने में लगी है कि व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक किनरा

जरूरत नहीं है और न ही इसका कोई विशेष मतलब निकाला जाना चाहिए।

मतदाताओं को जागरूक बनाने के विभिन्न अभियानों के लिए चुनाव आयोग को सभी चीजों का श्रेय मिलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों की पहल चुनाव आयोग ने की थी। इसके अलावा, मतदाता सूची को दोषरहित बनाने के लिए भी अभियान चलाए गए और इसीलिए काफी सारे फर्जी नाम इससे हट पाए। इन सबसे मतदान प्रतिशत में अच्छा-खासा इजाफा हुआ। लेकिन ठीक इसी समय में चुनाव आयोग को उन गलतियों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, जिनके चलते असली मतदाताओं के नाम हट गए, जबकि वे कई वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। इस तरह की शिकायतें सिर्फ एक-दो पोलिंग बुथों से नहीं, बल्कि कई पोलिंग स्टेशनों से आई हैं। हालांकि, यह समय चुनावों में जन-भागीदारी के बढ़ने के जश्न मनाने का है, लेकिन कुछ चुनाव अधिकारियों की लापरवाही के कारण मतदाता सूची से काफी लोगों के नाम का हट जाना भी चिंता की बात है।

बहरहाल, उच्च मतदान प्रतिशत दरअसल उस रुझान की ही निरंतरता है, जिसकी शुरुआत हाल के विधानसभा चुनावों में हुई थी। गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 फीसदी से अधिक टर्न-आउट रहा। दूसरे राज्यों, जैसे बिहार, कर्नाटक, मणिपुर और तमिलनाडु में यह वृद्धि सात-आठ प्रतिशत तक रही। लेकिन इस इजाफे का अधिक मतलब निकालना जोखिम भरा है, क्योंकि यह इस बात का आवश्यक संकेत नहीं कि भारी मतदान बदलाव के लिए ही हुए हैं। अतीत में हम देख चुके हैं कि विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कई सूबों में सत्तारूढ़

ऐसे चुनाव से क्या फायदा, जिसमें

मनोरंजन न हो। कम से कम हमारे देश में तो बेरिंग चुनाव नहीं ही लड़े जाते।

माफी और टॉफी की बहस के बीच एक नया

जुमला उल्टू बनने-बनाने का भी फिट कर दिया गया है। जो आजकल बेहद हिट है। हमें अपने देश के नेताओं का ‘एहसानमंद’ होना चाहिए कि उन्होंने चुनावी-राजनीति को गंभीरता से मुक्त करके उसे मनोरंजन युक्त बना दिया है। मतदात हर नेतल लगा हुआ है अपने-अपने तरीके से जनता का मनोरंजन करने और हमें लिखने का ‘मसाला’ देने में।

गुदुला सिन्हा	
	
बीबीसी में वर्तिका	
	
मेल बॉक्स	
	
गांव का हाल	
अमेठी के पास ही एक गांव है जायस, जो अब एक छोट कस्बे का रूप लेता जा रहा है। यहीं से कुछ दूर वीरान जगह पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी का घर है, जो अब लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। आलीशान कमरों में मकड़ी केजाले लग चुके हैं। दीवारें गिर रही हैं। रात के समय यह घर नशीदियों, जुआरियों और अन्य असामाजिक तत्वों की आशान-स्थली बन जाता है। अगर दिन में इस इमारत में जाएं, तो शराब की खाली बोतलें और नशीले पदार्थ मिलते हैं। मकान के आसपास मलबा और कूड़े-करकट का अंबार लगा हुआ है। जायस में विकास का कोई निशान नहीं दिखता। न तो केंद्र सरकार की नजर यहां पड़ी है, न ही	

राज्य सरकार की। अगर सब कुछ यों ही चलता रहा, तो यह ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाएगी।

जसवंत सिंह

शांतिकुंज, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग

आजकल जन-जागरूकता काफी बढ़ गई है, मीडिया की पैनी नजर है, इसलिए राजनेता अपने पुराने कारनामों पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकतर नेता अपने या अजीज लोगों के भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हैं। इसलिए इसमें से कुछ राजनेता भ्रष्टाचार को सामाजिक और कुछ वैश्विक समस्या बताते हैं। पर ये यह नहीं बताते हैं कि यह सामाजिक समस्या कहां से आई? ऐसे समय में, जब जनता यह जानने में लगी है कि व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक किनरा

जरूरत नहीं है और न ही इसका कोई विशेष मतलब निकाला जाना चाहिए।

मतदाताओं को जागरूक बनाने के विभिन्न अभियानों के लिए चुनाव आयोग को सभी चीजों का श्रेय मिलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों की पहल चुनाव आयोग ने की थी। इसके अलावा, मतदाता सूची को दोषरहित बनाने के लिए भी अभियान चलाए गए और इसीलिए मुझे लगता है कि जायज मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने से आयोग की छवि धूमिल हुई है।

मामला यहीं तक सीमित नहीं है। आदर्श आचार संहिता या चुनाव के नियमों के उल्लंघन के कई मामले बीते हफ्तों में सामने आए। इनसे निपटने को लेकर चुनाव आयोग की बेबसी से भी इस संस्थान की छवि को नुकसा पहुंच रहा है। चुनाव आयोग अधिक से अधिक यह कर पाया कि उसने उन राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों को कारण-बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था।

चुनाव आयोग की परवाह किए बगैर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं की सूची लंबी है और ऐसे नेता कई पार्टियों में हैं। उनमें से कुछ नाम हैं- बेनी प्रसाद वर्मा, अमित शाह, इमरान मसूद, आमज खान, वसुंधरा राजे सिंधिया, शरद पवार, गिरिराज सिंह, हेमा मालिनी, आशुतोष, अरविंद केजरीवाल। आखिरी वोट पड़ने तक यह सूची काफी बड़ी हो सकती है। सही मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने की जांच-पड़ताल के अलावा, चुनाव आयोग को इस समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

एक सामान्य नागरिक के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसे एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जाए। लेकिन एक उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग उसे मुकाबले का समान अवसर सुनिश्चित करए। एक तरफ, संविधान ने आयोग को स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने की पर्याप्त शक्तियां दी हैं। दूसरी तरफ, सामान्य मतदाता इस संस्थान के प्रति गहवा विश्वास प्रकट करते हैं। ऐसे में, चुनाव आयोग को दोनों मोर्चों पर काम करने होंगे। वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से ले और मतदाता सूची की गुणवत्ता को और दुरुस्त बनाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया

कब खत्म होगा पूर्वांचल के विकास का इंतजार

कोई भी राजनीतिक दल पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशेषताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनाता।

सदानंद शाही प्रोफ़ेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय	
	
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान होना है। देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट बनारस में मतदान इसी दौर में होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की चुनावी टक्कर ने इस लोकसभा सीट को बेहद दिलचस्प बना दिया है और इसका शोर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ क्षेत्रीय दलों की भागीदारी हो रही है, जो अलग-अलग वैचारिक मुखौटों के भीतर जाति और धर्म के समीकरणों से चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं।	

भारत की विविधता में एकता का खेल अपने-अपने ढंग से सभी राजनीतिक दल पीटते हैं, मगर चुनावी घोषणापत्र तैयार करते समय या विकास का एजेंडा तय करते समय विविधताओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में रॉबिन हुड छवि वाले नेताओं का बोलबाला रहा है। यहां लोकतंत्र की अलग-अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां काम करती रही हैं। कोई भी दल पूर्वी उत्तर प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक संरचना और भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाता। जाति और धर्म के झुनझुने थमाकर वोट के मसले तय हो जाते हैं। मूल समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के मूल में अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। यहां पर्याप्त शिक्षण संस्थान नहीं हैं। जो हैं, वे नीचे से ऊपर तक ध्वस्त हो गए हैं।

दागदार माननीय	
	
हमारे जन-प्रतिनिधि कितने स्वच्छ और ईमानदार होते हैं, इसका पता विभिन्न सामाजिक संस्थान लगाते रहते हैं। बहुत मुमकिन है कि इन संगठनों की निष्पक्षता पर कोई सवाल उठा दो। वैसे, हमारे जन-प्रतिनिधि ऐसे सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन हाल ही में आमिर खान के चर्चित कार्यक्रम ‘सत्यमेव जयते’ से हमें यह पता चला कि हमारी संसद और विधानसभाओं के 30 प्रतिशत से भी ज्यादा जन-प्रतिनिधि आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं। सचमुच, यह आंकड़ा हैरान कर देने लायक है। बेरत इस बात की है	

विजय लोढ़ा
रायपुर, छत्तीसगढ़

कि अधिकतर आपराधिक रिकॉर्ड वाले जन-प्रतिनिधि उस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने

आपको सबसे स्वच्छ और पाक-साफ बताती है। विश्व के सबसे बड़े

लोकतंत्र के लिए इससे अधिक शर्मांक स्थिति क्या हो सकती है कि

हमारे पूर्वजों का सपना उनके अपने देश के लोगों ने ही तात-तार कर दिया